शिक्षक - रवि शंकर राम, विषय - अर्थशास्त्र
दिनांक - 20-10-2020, वर्ग - BA-III

प्रश्न :- 'राजकीय पूँजीवाद' की नीति का परीक्षण कीजिये। इसका परित्याग क्यों किया गया?
Examine the policy of state capitalims. Why was it abandoned?

उत्तर :- नवम्बर 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद रूसी अर्थव्यवस्था में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गयी। पूँजीपतियों के मौत के घाट उतार कर श्रमिक औद्योगिक व्यवस्था को अपने कब्जे में करने लगे। चूँकि श्रमिकों को प्रबन्धीय अनुभव प्राप्त नहीं था, इसलिए औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई तथा औद्योगिक केन्द्रों में एक तरह का आतंक व्याप्त हो गया। कृषि क्षेत्र में स्थिति और भी अधिक भयावह थी बोल्शेविक क्रान्ति से पूर्व ही छोटे-छोटे किसान कुलकों को मौत के घाट उतार कर उनकी भूमि पर कब्जा करने लगे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त इस अराजकता को रोक पाने में प्रशासनिक तंत्र पूर्णतया असफल रहा। परिणामतः कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आई तथा देश में खाद्य-संकट उपस्थित हो गया। चूँकि बोल्शेविक पार्टी किसानों और मजदूरों के सहयोग से सत्तारूढ़ हुई थी, इसलिए

अपने समर्थकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करना संगठन पार्टी के लिए सम्भव नहीं था। दूसरी ओर क्रान्ति के परिणामों को स्थायी रूप देने के लिए आर्थिक व्यवस्था में उत्पन्न विघटन की रोकथाम भी आवश्यक थी। ऐसे विरोधाभासी स्थिति में लेनिन ने पूँजीवादी व्यवस्था से समाजवादी व्यवस्था की ओर अविलम्ब संक्रमण असंभव मानते हुए, अपनी पार्टी के राजनीतिक शक्ति सुदृढ़ बनाने के लिए, प्रतिक्रियावादी ताकतों के साथ समझौता किया तथा 'नियंत्रित पूँजीवाद' या 'राजकीय पूँजीवाद' की नीति अपनाई। यह नीति नवम्बर 1917 से लेकर जून 1918 तक केवल 8 महीने जारी रही।

राजकीय पूँजीवाद की व्याख्या — राजकीय पूँजीवाद की नीति का उद्देश्य उद्योगों पर ऊपर और नीचे दोनों ओर से राजकीय नियंत्रण स्थापित किया तथा अर्थव्यवस्था में विद्यमान विघटनकारी प्रवृति की रोकथाम करना था। इस नीति द्वारा सरकार ने स्वयं को तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप ढालने तथा नए सामाजिक विरोध

स्थापित करने का यथासम्भव प्रयास किया। सरकार द्वारा जारी की गई अज्ञप्ति में किसानों और मजदूरों से अपील की गई कि 'भूमि उद्यान, कारखानों, औजारों, उत्पादित वस्तुओं एवं परिवहन के साधनों की रक्षा आँख की भाँति करें तथा बहुमत की स्वीकृति तथा दैनिक जीवन के अनुभवों से शिक्षा ग्रहण करते हुए देश को शनैः शनैः समाजवाद की ओर ले जायें।

राजकीय पूँजीवाद या नियंत्रित पूँजीवाद की नीति के अन्तर्गत सोवियत सरकार की (क) भूमि-सम्बन्धी नीति तथा (ख) औद्योगिक नीति का समावेश, जिनका संक्षिप्त विवेचन निम्न प्रकार है—

(अ) भूमि-सम्बन्धी नीति ⇒ बोल्शेविक क्रान्ति को सफल बनाने में किसानों के असंतोष का प्रमुख ~~कारण था।~~ हाथ था। अतः अपनी राजनीतिक सत्ता को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए बोल्शेविक सरकार ने किसानों का समर्थन प्राप्त करना अनिवार्य समझा तथा किसानों के लिए 'शान्ति और भूमि की नीति' अपनाई। क्रान्ति से अगले ही दिन सरकार ने भूमि-सम्बन्धी अज्ञप्ति (Land Decree) जारी करके भूस्वामियों को बिना कोई मुआवजा दिए

समस्त प्रकार की भूमि (राजघरानों, महन्तों और गिरजाघरों की भूमि सहित) पर से उनका अधिकार समाप्त कर दिया। जब तक इस भूमि के पुनर्वितरण हेतु किसी स्पष्ट सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं हो पाए, तब तक के लिए भूस्वामियों की समस्त भूमि और कृषक-साधन (पशु, उपकरण, आदि) ग्रामीण समितियों और जिला समितियों को हस्तांतरित कर दी गयी परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाया तथा निकटवर्ती गाँव के किसानों ने आपस में ही भूमि का वितरण कर लिया। इस छीना-झपटी में बहुत से कृषि-साधन बर्बाद हो गए। राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारणों से सोवियत सरकार का भूसम्पत्ति के अराजक वितरण के प्रति मूक दर्शक बनी रही।

15 फरवरी 1918 को सोवियत सरकार ने अपनी भूमि-सम्बन्धी नई नीति की घोषणा की। इसके अन्तर्गत समस्त प्रकार की भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा किसानों के मध्य भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटने की व्यवस्था की गयी। नई नीति का उद्देश्य। कृषि का

'समाजीकरण' न होकर 'लघु कृषक-स्वामित्व' की स्थापना करना था। इस नीति के परिणाम स्वरूप किसानों के पास कृषि योग्य भूमि का अनुपात 70 प्रतिशत से बढ़कर 96 प्रतिशत हो गया तथा कृषि कार्य छोटे-छोटे उत्पादकों के हाथ नियंत्रण में चला गया। मार्च 1917 में स्थापित स्थाई सरकार द्वारा लागू की गई विधान के आधार में साम्यवादी एकाधिकार की नीति जारी रखी गई।